फरीदाबाद
मजदूर समाचार
मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

अपने बारे में, इस अखबार के बारे में बात करने आप किसी भी दिन मजदूर लाइब्रेरी आ सकते / सकती हैं।

नई सीरीज नम्बर 98 अगस्त 1996

बदहाली उपजाते मकड़जाल की झलक

एक बैलैन्सशीट की थोड़ी चीर-फाड़

पोर-पोर से चूस रहे, हमारी रग-रग को बेहाल कर रहे रक्त-पिपासुओं के ताने-बाने को जानने के लिये हम 7 जून के " जनसत्ता " अखबार में **एस्कोर्ट्स लिमिटेड** मैनेजमेन्ट की एडवरटाइजमेन्ट से कम्पनी की 1. 4. 94 से 31. 3. 95 की एक वर्ष की बैलैन्सशीट को यहाँ थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। आँकड़ों से चकरायें नहीं – यह तो मकड़जाल को काटने के लिये उसे समझने का जरिया मात्र हैं।

कम्पनी की बैलैन्सशीट के मुताबिक 31 मार्च 95 को समाप्त हुये वर्ष में एस्कोर्ट्स लिमिटेड में :

1422 करोड़ 74 लाख रुपये की कुल आमदनी और

1140 करोड़ 52 लाख रुपये का कुल खर्च हुआ।

इस प्रकार 282 करोड़ 22 लाख रुपये की कुल बचत हुई जिसकी हिस्सा-बाँट के बारे में बैलैन्सशीट बताती है :

153 करोड़ 42 लाख रुपये एक्साइज टैक्स (54.4 प्रतिशत)

20 करोड़ 25 लाख रुपये अन्य टैक्स (7.1 प्रतिशत)

39 करोड़ 90 लाख रुपये कर्ज पर ब्याज (13 प्रतिशत)

17 करोड़ 72 लाख रुपये घिसाई-डेप्रीसियेशन (6 प्रतिशत)

और, 50 करोड़ 93 लाख रुपये शुद्ध लाभ (18 प्रतिशत)।

सरकार का हिस्सा

एस्कोर्ट्स लिमिटेड की बैलैन्सशीट के अनुसार टैक्सों में ही सरकार ने 173 करोड़ 67 लाख रुपये लिये जो कि कुल बचत का साढे इकसठ परसैन्ट (61.5 प्रतिशत) बनता है।

यहाँ अधिकतर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें सरकारी हैं इसलिये कर्ज पर ब्याज का मुख्य हिस्सा भी सरकार की जेबों में जाता है। एस्कोर्ट्स लिमिटेड से सरकार ने 39 करोड़ 90 लाख रुपये ब्याज में लिये।

एस्कोर्ट्स लिमिटेड के आधे से ज्यादा शेयर एल आई सी आदि के नाम से सरकार के पास हैं। इसलिये कम्पनी के 50 करोड़ 39 लाख रुपये के शुद्ध लाभ में से शेयरों पर डिविडेन्ड के रूप में सरकार का हिस्सा आधे से ज्यादा बना। इसे 28 करोड़ 22 लाख रुपये मान लें तो यह कुल बचत का दस प्रतिशत बनता है।

इस प्रकार सरकार ने टैक्सों, ब्याज और शेयरों पर डिविडेन्ड के रूप में एस्कोर्ट्स लिमिटेड की 282 करोड़ 22 लाख रुपयों की कुल बचत में से 241 करोड़ 79 लाख रुपये लिये। यानि, **कम्पनी की बैलैन्सशीट के मुताबिक सरकार ने कुल बचत का साढे चौरासी परसैन्ट** (84.5 **प्रतिशत) हिस्सा लिया।**

जाहिर है कि 1400 करोड़ के कारोबार में से 240 करोड़ निकाल लेना काफी ज्यादा होता है परन्तु वास्तव में सरकार ने इससे भी बहुत अधिक लिये हैं। बैलैन्सशीट इन तथ्यों को उजागर नहीं करती कि मैनुफैक्चर में इस्तेमाल हुये स्टील जैसे "कच्चे" माल हों चाहे टायर-ट्यूब जैसे "कम्पलीट" माल हों – सरकार ने उन पर भी एक्साइज व अन्य टैक्स लिये हैं। बिजली-तेल-कोयले पर सरकार ने एक्साइज व अन्य टैक्स लिये हैं। ट्रान्सपोर्ट के बिलों में सरकार के एक्साइज व अन्य टैक्सों के पैसे शामिल हैं। .... किस-किस मद में और किस-किस आड़ में सरकारें टैक्स लेती हैं इसका पता करने और हिसाब लगाने को कहा जाये तो कम्प्युटर चकरा जायें।

मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एस्कोर्ट्स लिमिटेड द्वारा किये गये 1400 करोड़ के वार्षिक धन्धे में सरकार ने 700 करोड़ रुपये वसूले हैं। **कम्पनियों द्वारा किये जाते सालाना कारोबार में सरकारें विभिन्न टैक्सों के रूप में आधी से ज्यादा ही रकम हड़पती हैं।** .... कोई फिल्म मौजूदा व्यवस्था का बहुत पैनी मीठी छुरी की तरह पक्षपोषण करती है तब सरकार द्वारा "टैक्स फ्री" कर देने पर उसकी टिकट के दाम आधे से भी कम रह जाते हैं। सरकार द्वारा मनोरंजन टैक्स छोड़ने से यह होता है जबकि बाकि के अनगिनत टैक्स तब भी लागू रहते हैं।

सब्सिडी

इसलिये .... इसलिये **जब सरकार खाद या मिट्टी के तेल जैसे किसी मामले में सब्सिडी देने के ढोल पीटती है तब उसका मतलब मात्र यह होता है कि उस वस्तु पर लगाये 37 टैक्सों में से सरकार ने दो टैक्स छोड़ दिये हैं या कुछ कम कर दिये हैं।** हर वस्तु, हर अवस्तु (अंग्रेजी में कहेंगे non-thing) पर सरकारें विभिन्न टैक्स लेती हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी देने का अर्थ वही है कि 1000 ले कर कोई 10 लौटाये और कहे कि 10 दिये हैं!

वास्तव में सरकारें ही नहीं बल्कि मैनेजमेन्टें भी सब्सिडी लेती हैं। तभी तो भारत सरकार फौजों पर ही हर साल तीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। तभी तो यहाँ चप्पे-चप्पे को रौंदती विभिन्न प्रकार की पुलिस पर सरकारी खर्च बीस हजार करोड़ रुपये है और फिर चालीस हजार करोड़ रुपये पुलिसवाले हर साल नागरिकों से विभिन्न सब्सिडियों के तौर पर यूँ भी वसूल लेते हैं। मंत्रियों-अफसरों द्वारा ली जाती सब्सिडियाँ .... **यह रकमें मजदूरों व अन्य मेहनतकशों पर खर्च होने लगें तो ?**

मैनेजमेन्ट का हिस्सा

282 करोड़ 22 लाख रुपये की कुल बचत में से सरकार का हिस्सा तथा घिसाई के पैसे निकाल देने पर 22 करोड़ 71 लाख रुपये ही बचते हैं। यह कुल बचत का मात्र आठ प्रतिशत है और इसके हिस्सेदार हजारों शेयर होल्डर हैं। कम्पनी का चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नन्दा इन शेयर होल्डरों में एक है और नन्दा परिवार के पास एस्कोर्ट्स लिमिटेड के पाँच परसैन्ट से भी कम शेयर हैं। चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर को शेयरों से मिलती रकम उसके लिये ऊँट के मुँह में जीरा है।

जाहिर है इत्ती-सी रकम के लिये नन्दा परिवार चेयरमैन - मैनेजिंग

(बाकी पेज तीन पर)

गीत

हेइसा रे हेइसा ....
जोर लगा हेइसा ....
सब कुछ कर पर
माँग मत पइसा .... !
देस का सवाल है
ये कौम का सवाल है।
बड़ी खत्तियों का
मौटी तौंद का सवाल है।
घूम प्यारे घूम तू
घानी के बैल जइसा.... ! हेइसा रे ....
बच्चे तेरे भूखे और
रोगी है महरिया।
बोझा ढोते बीती रामा
सिगरी उमरिया।
फिर भी अनुशासन में
बाजी मार गया भैंइसा.... ! हेइसा रे ....
शास्त्र का कथन है
ये गीता का वचन है।
फल की मत आस कर तू
काम ही धरम है।
रोटी भी नसीब नहीं
हलवा-माँडा कइसा.... ! हेइसा रे ....
टूटी हुई चप्पल अपनी
फटा हुआ कुरता।
इतना किया काम भैया
निकल गया भुरता।
अब जैसी तेरी तूमड़ी
अपना भी नाच वइसा.... ! हेइसा रे ....

—महेन्द्र नेह, कोटा (राजस्थान)

ग़ज़ल

जिसकी ऊँची दुकान है यारो
उसके फीके में जान है यारो

हम अगर सिर के बल खड़े हो लें
ये ज़मीं आसमान है यारो

मेरी नज़रों से आसमां देखो
सिर्फ नीला निशान है यारो

झूठ समझे-कि आसमां से गिरे
पहली ही पायदान है यारो

जिनका दफ्तर में आना-जाना है
उनकी मुश्किल आसान है यारो

छत पे खड़िया से लिख दिये नारे
सारी बस्ती महान है यारो

तुमको लगता है ये है मेरी ग़ज़ल
हर किसी का बयान है यारो।

— संजय ग्रोवर, हाथरस (उ0 प्र0)

नया वरकर

जो बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ वह बात पिछले महीने की है जब मैं **ब्रॉन लेबोरेट्रीज** में काम करता था। इस कम्पनी के कुछ ऐसे कानून हैं जो कुछ वरकरों पर लागू होते हैं और कुछ पर नहीं। जब मैं यहाँ पहली बार नौकरी पाने के लिये गया तो मुझे पता चला कि यहाँ केवल उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है जिनके पास किसी की सिफारिश हो। तब 22 मई को एक की सिफारिश ले कर मैंने मिस्टर हंस से मिलने की कोशिश की मगर मैं उन्हें मिल नहीं पाया। उन्होंने मुझे 24 तारीख को आने को कहा। मैं वहाँ ठीक दिनांक को गया और मिस्टर आर पी हंस से मिला जिन्होंने मुझे 1. 6. 96 को आने को कहा।

मैं वहाँ 1 तारीख की बजाय 3 को पहुँचा क्योंकि 3 तारीख को सोमवार था। मैं हंस जी से मिला। उन्होंने मुझे उसी दिन से नौकरी पर रख लिया। उन्होंने मुझे वहाँ की वर्दी-चप्पल इत्यादि दिये। पहले दिन उन्होंने मुझे पेटियाँ लोडिंग पर लगाया। धीरे-धीरे मैंने वरकरों से जान-पहचान बढाई और उनसे कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा है। 150 वरकर ठेकेदार के हैं और बाकी 50 परमानेन्ट हैं। ठेकेदार 786 सैक्टर--9 में बैठता है। यह बात सुन कर मुझे अपना इतिहास याद आया। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब अंग्रेज भूमि को ठेकों पर ठेकेदारों को देते थे। लेकिन आजादी के बाद यह प्रथा कम्पनियों में चल गई। यह प्रथा करीब-करीब सभी कम्पनियों में चल रही है।

4 जून को शाम को उन्होंने मुझे सैक्टर--9 ठेकेदार के पास भेजा। वहाँ ठेकेदार ने मेरा नाम-पता इत्यादि लिखा और एक कार्ड दे कर मुझे वापस भेज दिया। इस कम्पनी में काम करते हुये मुझे पता चला कि यहाँ पर जो परमानेन्ट वरकर हैं केवल उन्हीं की इज्जत है, ठेकेदार के मजदूरों की कोई इज्जत नहीं है। मुझे पता चला कि एक बार एक ठेकेदार के वरकर की उँगली कट गई जिस पर उसे सहानुभूति की जगह डाँट मिली और उसे कम्पनी ने हिसाब दे कर निकाल दिया। एक हादसा मेरे सामने हुआ। एक परमानेन्ट का हाथ मशीन में आ गया। मामूली-सा घाव हुआ। पूरा स्टाफ और वरकर उसका हालचाल पूछने लगे। इस प्रकार यहाँ ठेकेदार के वरकरों की कोई इज्जत नहीं। उन्हें छोटी-सी बात पर भी निकाल दिया जाता है। अगर यहाँ ठेकेदार का कोई मजदूर 8.15 तक नहीं पहुँच पाया तो उसे बाहर कर दिया जाता है जबकि कम्पनी में कार्य 8.30 पर चालू होता है। यही हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैं एक दिन कम्पनी 8.20 पर पहुँचा तो उस दिन उन्होंने मुझे नहीं लिया और गेट से बाहर कर दिया।

एक दिन की बात है कि कंम्पनी ने मुझे एक लड़के की जगह पर कैन्टीन में भेज दिया। जब मैंने उस लड़के का जिक्र किया जो वहाँ पहले था तो मुझे पता चला कि एक दिन उसने जरूरी काम पड़ने पर छुट्टी कर ली और अगले दिन जब वह आया तो कम्पनी ने उसे काम पर नहीं लिया और उसको हिसाब दे दिया। उस लड़के की जगह काम करने से मुझे पता चला कि यहाँ स्टाफ में 60 लोग हैं और उन सब के लिये दो टाइम चाय बनती है लेकिन वरकरों के लिये यहाँ ओवर टाइम में भी चाय नहीं बनती। यहाँ पर वरकरों के साथ भेदभाव किया जाता है।

कुछ वरकरों से मुझे पता चला कि कम्पनी ने दो आदमियों को यहाँ पर होने वाले दँगों को या जब यहाँ भर्ती होती है तब यहाँ लड़ाई इत्यादि को रोकने के लिये रखा हुआ है।

एक दिन मुझे दिल्ली फोन करना था तो मुझे पता चला कि वरकरों को यहाँ फोन करने की इजाजत नहीं है। 19 दिन काम करने के बाद जरूरी काम के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मैं दो दिन की छुट्टी ले कर गया। वहाँ से आया तो मुझे कम्पनी में नहीं जाने दिया और मेरा हिसाब बना कर मुझे 9 सैक्टर भेज दिया। वहाँ हिसाब लिया तो मुझे पता चला कि यहाँ पी एफ और ई एस आई भी कटते हैं। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया क्योंकि यह कानून सभी पर लागू था। यहाँ पर पेमेन्ट 1410 रुपये है जिसमें से 10 प्रतिशत पी एफ और 2 प्रतिशत ई एस आई कटता है।

निकाल दिये जाने के बाद मैं घर पर बेरोजगार बैठा हूँ और किसी दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ।

5 जुलाई 96 — दीपक

हिसाब-किताब रखने वालों के मुताबिक अब दुनियाँ के सब देशों का हथियारों पर प्रतिवर्ष खर्च 600 बिलियन डालर है। रुपयों में यह रकम 21,000,000,000,000 रुपये है। देश, देश की रक्षा, देशभक्ति कैसी चीज हैं?

हरियाणा के गाँवों में

सभी खातियों (चिनाई करने वालों) ने मिल-बैठ कर बिना बिचौलियों के अपनी दिहाड़ी 150 रुपये प्रतिदिन कर दी है। जिसको अपना काम बढिया करवाना होता है और पूरा करवाना होता है वह 150 रुपये के अतिरिक्त दो वक्त की रोटी के साथ दो वक्त चाय व तम्बाकू भी पिलाता है तथा अपने परिवार के बुजुर्गों के समान आदर-सत्कार भी देता है।

आम मजदूर 80 रुपये से कम बात नहीं करता।

यदि अनाज की एक बोरी को बुखारी में से छान कर, भर कर व तोल कर एक घर से दूसरे घर तक लाया जाता है तो 10 रुपये प्रति बोरी लिया जाता है।

यदि कोई अपना खेत बटाई पर देना चाहे तो अनाज (फसल) का आधा लिया जाता है और अब तो आधा खर्चा भी मालिक से लिया जाने लगा है।

मजदूरों ने काम के घन्टे भी छह से आठ कर दिये हैं।

इस सब को करने में न तो किसी बिचौलिये की आवश्यकता पड़ी और न किसी मंत्री-अफसर की मेहरबानी की।

4. 7. 96 — एक अध्यापक

चन्डी का जादू

पहली जुलाई को मैनेजमेन्ट ने नोटिस लगाया कि 10 जुलाई तक स्वेच्छा से नौकरी छोड़ो और कुछ एक्स्ट्रा लो। नौकरियों के लिये मिन्नतों - रिश्वतों के इस दौर में राजी से रिजाइन भला कौन करेगा ? स्वेच्छा से न सही, अनिच्छा से रिजाइन करवाने के लिये **ईस्ट इंडिया कॉटन मिल** मैनेजमेन्ट ने 11 जुलाई को अजन्ता टेबल प्रिन्टिंग तथा उसके कलर रूम में तालाबंदी कर दी और इनके मजदूरों को जून का वेतन भी नहीं दिया। इसके बावजूद बाकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन सामान्य तौर पर जारी देख कर मैनेजमेन्ट खुशी से झूम उठी। अजन्ता खाते के वरकरों को दस दिहाड़ियों की चपत लगा कर 18 को चन्दीगढ में लेबर कमिश्नर- मैनेजमेन्ट - लीडर मीटिंग के बाद 19 को तालाबंदी उठा ली गई और मैनेजमेन्ट ने नोटिस लगा दिया कि स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की तारीख 31 जुलाई तक बढा दी गई है।

दरअसल एक साल से ईस्ट इंडिया मैनेजमेन्ट टेबल प्रिन्टिंग पूरी तरह खत्म करने के लिये छह-सात सौ मजदूरों को निकालने की फिराक में है। पूरी फैक्ट्री में तालाबन्दी करके तथा एक लीडर को उछाल कर उसके जरिये छँटनी करने की मैनेजमेन्ट की एक बड़ी स्कीम फेल हो चुकी है। इधर मैनेजमेन्ट नये लीडरों को उभार कर 600 मजदूरों को निकालने का जाल बुन रही है। चन्दीगढ के साहबों ने बढिया एग्रीमेन्ट की आड़ में कल्चिनेटर मैनेजमेन्ट को ढाई हजार मजदूरों को निकालने की राह पर आगे बढाया और चन्डी के इस जादू को ईस्ट इंडिया में दोहराये जाने की काफी सम्भावना है।

1979 में आटोमेशन के लिये मैनेजमेन्ट को ढाई-तीन हजार मजदूर निकालने थे। तब लीडरों ने जो भी कहा ईस्ट इंडिया के मजदूरों ने वही किया। वरकरों ने बहुत तकलीफें झेली परन्तु नतीजा दुखद रहा।

मजदूरों द्वारा किसी के कहने पर उठना - बैठना - चलना - मुड़ना - रुकना मैनेजमेन्टों के काम को आसान बनाता है। परन्तु ईस्ट इंडिया के सब मजदूर विचार-विमर्श व फैसले लेने में साझीदार बन कर चन्डी के जादू को काट सकते हैं, 600 नौकरियाँ बचा सकते हैं।

इस समय ईस्ट इंडिया में मुख्य मुद्दा छँटनी है। अभी एग्रीमेन्ट मुख्य मुद्दा नहीं है। 1979 में भी छँटनी मुख्य मुद्दा था लेकिन हड़ताल बोनस के लिये की गई थी ! ■

कागजी सबूत

जुलाई अंक लेते समय **इंडियन हार्डवेयर इन्डस्ट्रीज** के एक मजदूर ने बताया कि मैनेजमेन्ट तनखा 1040 रुपये देती है और वरकरों से दस्तखत 1410 पर करवाती है ताकि न्यूनतम वेतन कानून के पालन करने का दस्तावेजी सबूत रख सके। इंडियन हार्डवेयर का मजदूर चाहता था कि यह बात हम अखबार में छापें। उस वरकर ने यह भी बताया कि वेतन 7 तक देने की बजाय मैनेजमेन्ट 14 के बाद देती है परन्तु कागजों पर 7 तारीख को वेतन देना दिखा कर कानून के पालन का दस्तावेजी सबूत रखती है। ■

जून और फिर जुलाई अंक में छपे "एकता बनाम सामुहिकता" लेख पर अपनी राय देना कृपया जारी रखें। इस अंक में इस सम्बन्ध में हम फिर एक मजदूर के विचार देना चाहते थे पर जगह की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सके। अगले अंक में यह जरूर देंगे।

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक–एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

कविता

आँधियों में जो जलता हुआ मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

जब कभी आओगे यारो मुल्क मेरा देखने
वो यतीमों की तरह सहमा हुआ मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

कागजों पर मुल्क का नक्शा बनाना छोड़ दो
वरना हर शख्स इसको काटता मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

यह मुमकिन नहीं हर जिस्म में हो मेमना
मगर हर जिस्म में इक भेड़िया मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

मैंने सोते वक्त ये सोचा न था कि ख्वाब में भी
भूख से बेहाल बच्चा जागता मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

आँधियों में जो जलता हुआ मिल जायेगा
उस दिये से पूछना मेरा पता मिल जायेगा।

– ममता, फरीदाबाद

बैलैन्सशीट की थोड़ी चीर-फाड़ (पेज एक का शेष)

डायरेक्टर बनने के लिये इतने पापड़ नहीं बेलता। सरकार के लिये कामधेनु पालने के लिये नन्दा परिवार अपने मन-विवेक को कदम-कदम पर गिरवी नहीं रखता।

दरअसल 1400 करोड़ रुपये की खरीद - बिक्री - ठेकों पर ही सीधी-सादी 15 परसैन्ट कट-कमीशन-रिश्वत की रकम दो सौ करोड़ रुपयों से अधिक बनती है। इस रकम का बैलैन्सशीट जिक्र तक नहीं करती। मैनेजमेन्ट में नीचे से ऊपर की तरफ उठते जाने के साथ इस रकम में हिस्सा-पत्ती बढती जाती है। इस रकम में से बड़ा हिस्सा लेने के वास्ते ही मैनेजमेन्ट प्रमुख बनने के लिये, कम्पनियों के चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिये इतनी मारा-मारी होती है।

कोई मालिक नहीं है

बैलैन्सशीट के अनुसार एस्कोर्ट्स लिमिटेड की शेयर पूँजी तब 33 करोड़ 90 लाख रुपये थी। कर्ज पर कम्पनी ने जो ब्याज दिया उससे हिसाब लगायें तो एस्कोर्ट्स लिमिटेड ने 250 करोड़ रुपये कर्ज लिया हुआ था। कम्पनी की शेयर पूँजी की रकम कर्ज़ के पैसों के छठे हिस्से से भी कम ! **कम्पनियों का कारोबार मुख्यतः कर्ज के पैसों से होता है।**

एस्कोर्ट्स लिमिटेड के निर्माण व संचालन में 283 करोड़ 90 लाख की जो रकम लगी थी उसका 86 परसैन्ट हिस्सा कर्ज है। नन्दा परिवार के तो शेयरों तक में पाँच परसैन्ट से कम हैं इसलिये कम्पनी में लगी कुल राशि में नन्दा परिवार का हिस्सा एक प्रतिशत के आधे से भी कम है। अतः एस्कोर्ट्स लिमिटेड का चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नन्दा कम्पनी का मालिक नहीं है। **कम्पनियों के अब कोई मालिक नहीं हैं।**

सब को ढोते मजदूर

अब काम इतनी तीव्रता व तीक्षणता से होता है कि अपनी तनखा के पैसे तो वरकर 15 मिनट के काम द्वारा पूरे कर देता/देती है। आठ घन्टे की शिफ्ट में बाकी के साढे सात - पौने आठ घन्टे मजदूर टैक्स - ब्याज - कट/कमीशन/रिश्वत-ट्रेडहिस्सा-मुनाफे के लिये खटते/खटती हैं। ■

एकता बनाम सामुहिकता

सामुहिकता और एकता एक-दूसरे के उलट हैं। मजदूरों का लीडरों के पीछे चलना एकता है। मजदूरों द्वारा सोच-विचार कर मिल-जुल कर राजी से कदम उठाना सामुहिकता है। मैनेजमेन्टों और लीडरों के काम की है एकता। मजदूरों के हित सामुहिकता में हैं।

सामुहिकता की झलक

★ निचुड़ने के बाद फैक्ट्री से निकलने के समय तलाशी द्वारा हर रोज हर मजदूर अपमानित किया जाता/जाती है। **एस्कोर्ट्स ग्रुप** के **फोर्ड प्लान्ट** में चीरे पर नमक छिड़कते हुये मैनेजमेन्ट ने 13 जुलाई को मजदूरों की स्कूटरों-मोटरसाइकिलों की भी तलाशी लेनी शुरू कर दी जबकि घिरी जगह पर यह मैनेजमेंट के ताले के अन्दर रहती हैं। मजदूरों में गुस्सा बढा और नाइट में सी शिफ्ट वाले सब वरकर 14 को सुबह 8 बजे फैक्ट्री से निकलने की बजाय गेट पर इकट्ठे हो गये। 14 को रैस्ट का दिन था पर मैनेजमेंट ने सिंगल रेट से ओवर टाइम पर मजदूर बुलाये थे। इससे उस सन्डे फैक्ट्री गेट के दोनों तरफ लम्बी-लम्बी कतारें लग गई। दस बज गये। एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और स्कूटरों-मोटरसाइकलों की तलाशी का कदम वापस लेना पड़ा।

ओवर टाइम पर आये मजदूरों ने तब मैनेजमेंट से कहा कि 8 बजे से हाजरी लगाते हो तो ड्युटी करेंगे नहीं तो वापस जा रहे हैं। एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट को फिर झुकना पड़ा और उसने 8 बजे से हाजरी लगाने की बात मानी हालांकि प्रोडक्शन का काम 10 बजे के काफी बाद में शुरू हुआ।

★ मजदूरों की हाउसिंग की जमीन की बिक्री में भारी रकम हड़पी गई पर फिर भी जमीन बेचने के 8 महीने बाद भी काफी वरकरों को मैनेजमेन्ट ने जमीन के पैसे नहीं दिये। पाँच महीनों का वेतन भी बकाया .... 13 जुलाई को **झालानी टूल्स फस्ट प्लान्ट** में मजदूरों ने इकट्ठे हो कर मैनेजमेन्ट को घेरा। साहबों के रिसेप्शन में बैठे लीडरों ने सोमवार, 15 तारीख को हाउसिंग के पैसे देने का आश्वासन दे कर मैनेजमेन्ट को मजदूरों के घेरे से निकाला। 15 को पैसे नही दिये। 15 को शाम को मजदूरों ने इकट्ठे हो कर मैनेजमेन्ट को फिर घेरा। साहबों के बचाव में लीडर फिर आगे आये। मजदूरों ने लीडरों और साहबों को खूब खरी-खरी सुनाई। 16 जुलाई से मैनेजमेन्ट ने हाउसिंग के पैसे मजदूरों को बाँटने शुरू कर दिये।

★ वर्क लोड बढाने का विरोध कर रहे पैकरों की सामुहिकता तोड़ने के लिये **बाटा** मैनेजमेन्ट ने दो पैकर 8 महीने सस्पैन्ड करने के बाद डिसमिस कर दिये। पैकरों की सामुहिकता तो बरकरार रही ही, बाटा फैक्ट्री के अन्य मजदूरों में भी सुगबुगाहट बढी। इस पर अपनी ही नहीं बल्कि नये-पुराने लीडरों की भी अनिच्छा के बावजूद मैनेजमेन्ट ने डिसमिस पैकरों को ड्युटी पर लिया पर दो दिन बाद उन्हें फिर निकाल दिया। परन्तु बाटा मजदूरों की सामुहिकता के खतरे का हिसाब लगा कर मैनेजमेन्ट को झख मार कर 15 दिन बाद डिसमिस वरकरों को नौकरी पर रखना ही पड़ा।

एकता के गुल

★ दिल-दिमाग के अनुसार चल कर **एस्कोर्ट्स के सब प्लान्टों** में मजदूर सामुहिक कदम उठाते रहते हैं और सफलतायें प्राप्त करते रहते हैं परन्तु जब बड़े मुद्दे सामने आते हैं तब बेमन से ही सही पर अन्य मजदूरों की ही तरह एस्कोर्ट्स वरकर भी अक्सर एकता के भंवरजाल में लौट जाते हैं, लीडरों के कहे अनुसार उठने-बैठने लगते हैं। एकता में लौटने, लीडरों के पीछे चलने का एक नतीजा यह है कि कानून तक ओवर टाइम पेमेन्ट डबल रेट से देने का है परन्तु लीडरों ने कुछ वर्ष पहले सिंगल रेट की एग्रीमेन्ट की और अब फरीदाबाद स्थित एस्कोर्ट्स के सब प्लान्टों में मजदूरों को ओवर टाइम के पैसे मैनेजमेन्ट सिंगल रेट से देती है।

★ ठोकर पर ठोकर खा कर **झालानी टूल्स** के मजदूरों ने एक के बाद दूसरे लीडर गिरोह को हटाया है। सामुहिक कदमों की सफलतायें भी इन मजदूरों ने चखी हैं परन्तु एकता की पैठ बहुत गहरे तक है। झालानी टूल्स वरकरों में एकता बरकरार रहने, मजदूरों द्वारा किसी-न-किसी लीडरशिप के पीछे चलना जारी रखने का ही नतीजा है कि हर वरकर के बकाया वेतन आदि के 15–20 हजार रुपये हो जाने के संग-संग मजदूरों के सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे भी डूबने की नौबत आ गई है।

★ डिपार्टमेन्ट स्तर पर अक्सर और जब-तब फैक्ट्री स्तर पर सामुहिकता के मीठे फल **बाटा** मजदूरों ने भी चखे हैं परन्तु वरकरों के सामुहिक कदमों की एकता वाले लोग, लीडर लोग बाटा में बहुत भर्त्सना करते हैं। और, ढेरों काँटों-चीरों वाले अनुभवों के बावजूद बाटा वरकरों में एकता बरकरार है, लीडरों के कहे अनुसार चलना (बेमन से ही सही) जारी है। नतीजतन, धड़ल्ले से वेतन काटती आ रही बाटा मैनेजमेन्ट ने अब कान पकड़ कर मजदूरों को कभी इस डिपार्टमेन्ट तो कभी उस डिपार्टमेन्ट में भेजना शुरू कर दिया है।

★ इस साल पहली फरवरी से मैनेजमेन्ट के फैक्ट्री नहीं आने के बाद भी **इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड** के मजदूरों में एकता बरकरार रही, लीडरों के आदेशानुसार वरकर बैठते और उठते रहे। लीडरों के एक के बाद दूसरे आश्वासन के थोथा साबित होने के बाद भी इलेक्ट्रोनिक्स वरकरों ने एकता कायम रखी है, लीडरों के पीछे चलना जारी रखा है। नतीजा है इन छह महीनों में इलेक्ट्रोनिक्स मजदूरों का बिखर जाना और हालात उनके बकाया वेतन, बकाया पी एफ के संग-संग सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे डूबने के बन गये हैं।

★ 1983 में मैनेजमेन्ट द्वारा बन्द की गई **ईस्ट इंडिया ग्रुप की जूट मिल** के 900 मजदूरों को सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे आज तक नहीं मिले हैं। जूट मिल मजदूरों के पैसे लीडरों के पीछे चलने पर, एकता पर न्यौछावर हो गये हैं। ■

" हमारे बारे में नहीं देते "

जुलाई अंक लेते समय **रोलाटेनर** फैक्ट्री के एक मजदूर ने शिकायत की कि रोलाटेनर के बारे में हमने अभी तक कुछ भी नहीं छापा है जबकि इस फैक्ट्री में बहुत धाँधलेबाजी है। **अमेटीप मशीन टूल्स** के एक मजदूर का उलाहना था कि अखबार में एस्कोर्ट्स, केल्विनेटर आदि के बारे में तो खूब छपता है परन्तु अमेटीप के बारे में कुछ भी नहीं। **इन्जेक्टो लिमिटेड** के मज़दूरों को शिकायत थी कि एक बार थोड़ा-सा छाप कर हमने फिर कभी इन्जेक्टो के बारे में कुछ नहीं दिया। **लखानी शूज** के एक वरकर ने कहा कि कम्पनी में बहुत अनीति है फिर भी लखानी शूज की बदमाश मैनेजमेन्ट के बारे में हम कुछ नहीं छापते। **आयशर ट्रैक्टर** के **अप्रेन्टिस वरकर** इस बात पर नाराज़ थे कि उन्होंने चार दिन हड़ताल की पर अखबार में हमने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। **निक्कीताशा** फैक्ट्री के एक मजदूर ने अखबार लेते समय कहा कि निक्कीताशा के बारे में तो हम कुछ छापते ही नहीं...

बता दें - याद दिला दें - दोहरा दें कि इस अखबार के कोई संवाददाता, कोई पत्रकार नहीं हैं। यहाँ फरीदाबाद स्थित फैक्ट्रियों में ही मजदूरों के लिहाज से हर रोज हजारों महत्वपूर्ण घटनायें होती हैं परन्तु उनके सौंवे हिस्से की जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती। आमतौर पर मजदूर खुद जो बताते हैं वही हम अखबार में दे पाते हैं। अपनी बात छपवाने के आपके कोई पैसे नहीं लगते। और हाँ, जो मजदूर अपनी बात छपवाते हैं उनके नाम हम किसी को नहीं बताते। अपनी बात हमें मिल कर बतायें या खत डाल दें।

पता है – मजदूर लाइब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
फरीदाबाद–121001

फिर जिक्र कर दें कि अखबार को बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। जो वरकर पैसे देना चाहते हैं वे अखबार लेते समय बेझिझक पैसे दे सकते हैं। ■

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।